Defence Research and Production Cooperation

6. Defence research and production cooperation will also be an integral part of our bilateral defence relationship. Existing technical and production co-operation activities, such as the cooperation in India's Light Combat Aircraft (L.C.A) programme, have been encouraging will be continued. The scope and content of further expansion of co operative defence research and production activities, in accordance with the laws, policies and agreements of each country, will be developed by a Joint Technical Group (JTG) composed of senior professionals from the two countries. To ensure consistency with the development of the overall bilateral relationship, the MOD-OSD Policy Group will provide appropriate policy guidance to the JTG. The first JTG meeting will follow the MOD-OSD Policy Group meeting scheduled for Spring of 1995.

Protection of Classified Information

7. In order to promote defence co-operation
activities, the two sides will begin early consultations with a view to arriving at a bilateral agreement on the mutual protection
of classified information.

Signed at New Delhi on January 12, 1995 in two copies in English, each being equally outhentic.

FOR AND ON BEHALF
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF OF THE GOVERNMENT OF THE INDIA UNITED STATES OF AMERICA

लोक-नायक सेतु के निर्माण को पूरा किया जाना

671. **श्री राम जेठमलानी** :

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या दिल्ली में यमुना नदी पर कई वर्षो से निर्माणाधीन लोक-नायक सेतु के 1996 के अंत तक बनकर पूरा हो जाने की संभावना हैं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी राशि व्यय होने का अनुमान हैं तथा यह राशि परियोजना की मूल निर्माण-लागत से कितनी अधिक हैं;

(ग) क्या यह भी सच हैं कि इस परियोजना के अंतर्गत सेतु के दोनों ओर सड़कों का अतिरिक्त निर्माण करने का प्रावधान किया गया था ताकि इस सेतु का समुचित उपयोग हो सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और उन सड़को का निर्माण नहीं करने के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजसेकर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) इस परियोजना की संस्वीकृत राशि 2578 लाख रू. है और इस पर 4420 लाख रू. की लागत आने की संभावना हैं।

(ग) जी हां।

(घ) पुल के दोनों ओर सड़को के निर्माण का प्रावधान हैं। इन सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं और पुल के साथ इसके पूरे हो जाने की उम्मीद हैं।

दिल्ली में अपराधियों द्वारा कारों में रंगीन शीशे का कथित प्रयोग

672. **श्री नागमणि** :

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़को पर अपराधी रंगीन शीशे वाली कारों में घूम रहे हैं;

(ख) दिल्ली में कारों के शीशे कितने प्रतिशत पारदर्शी होने चाहिए;

(ग) क्या पुलिस के पास ऐसे शीशे की पारदर्शिता मापने के लिए कोई उपकरण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो.एम. कामसन) : (क) दिल्ली में पिछले छह महीनों, अर्थात् 1.8.95 से 28.2.96 तक के दौरान ऐसा कोई मामला सूचित नहीं हुआ हैं।

(ख) मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 100(2) के उपबन्धों के अधीन, प्रत्येक मोटर-वाहन के विण्ड स्क्रीन और खिड़कियों के शीशे ऐसे होने तथा बनाए रखे जाने चाहिए कि वे पूर्णत: पारदर्शी हों तथा जिसके अन्दर से बाहर तथा बाहर से अन्दर स्पष्ट दिखाई देता हो।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के परिवहन विभाग ने इस मामले की विस्तार से जांच की हैं तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190 (1) के अधीन ऐसी सोलर फिल्म/रंगीन शीशे वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्णय लिया हैं जिनकी पारदर्शिता 70 प्रतिशत से कम होगी।

(ग) और (घ) किसी मोटर वाहन के रंगीन शीशों की पारदर्शिता की प्रतिशतता की जांच लक्स मोटर की सहायता से तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की जा सकती हैं। इस समय दिल्ली यातायात पुलिस के पास ऐसी उपकरण सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिल्ली पुलिस को यह उपकरण तथा तकनीकी विशेषता उपलब्ध कराने के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया हैं।

Allocation of PCO to Educated Unemployed Youth

673. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government allot Payphones/PCOs to unemployed youth on priority basis throughout the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of educated youth under this category who were allotted Payphones/PCOs on priority in Nagpur district of Maharashtra during the last three years, with year-wise details; and

(d) the number of such PCOs which are likely to be released to the district during the remaining period of the Eighth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir,

(b) The required information is given in statement I *(See* below).

(c) The required inforamation is given in statement II *(See* below).

(d) About 500 PCOs are likely to be released in Nagpur Telecom Distt, during the remaining period of the Eighth Five Year Plan.

Statement-I

STD/ISD/PCOs.

1. Eligibility

Only educated unemployed persons are eligible to apply for allotment of STD/ PCOs. They should produce an unemployment certificate from their local MPs/ MLAs— Revenue authorities of the rank of Tehsildar and above/employment officer/Chairman or Member of Zilla Parishad/Panchayat or Village Pradhan or Secretaries of recongnised Social Organisations like Rotary Club/Lions Club etc. who have jurisdiction over the locality where the applicant resides. The educational qualifications for applicants are:—

(i) for rural areas: 8th or middle school pass and above.

(ii) for urban areas: atleast matriculate or High School and above.

Application is to be submitted in the presbribed proforma enclosing the unemployment certificate and agreeing to the terms and conditions prescribed by the Department of Telecom., for the operation of STD/PCOs.

2. Selection of bonafide persons.

A Committee with a composition as given below will select the applicants for allotment of STD/PCOs after proper scrutiny and verification of bonafides. As a Check against possible frauds, photocopy of the unemployment certificate may be sent by registered letter to the issuing authority with a covering letter requesting for getting it verified. The Committee will allot the available number of PCOs giving preference to following categories of persons:

(a) Handicapped including blind persons.

(b) SC/ST applicants.

(c) Ex-servicemen/War Widows.

(d) Retired DOT employees or their dependents.

(e) Freedom Fighters or their dependents.

(f) Charitable Institutions/Hospitals.

The Committee will be fully authorised to